लखनऊ के विवेक तिवारी हत्याकांड पर काली पट्टी बांधकर कुछ पुलिसजन द्वारा किया गया विरोध, अनुशासनहीनता है

विजय शंकर सिंह

पुलिस में आदेश का अनुपालन न करने और कायरता प्रदर्शित करने का एक ही दंड है, वह है सेवा से बर्खास्तगी। यह पुलिस में ही नहीं बल्कि सभी यूनिफॉर्म सुरक्षा बलों में है, यहां तक कि सेना में भी। अभी विवेक तिवारी हत्याकांड में दोषी पुलिसजन पर सरकार ने कार्यवाही की है और एसआईटी द्वारा जांच भी हो रही है। पर कुछ पुलिस वालों का अभियुक्तों के समर्थन में काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन करना और उसे सोशल मीडिया पर डालना, यह एक असामान्य बात है। अपने 34 साल के पुलिस जीवन मे ऐसा न तो मैंने देखा है और न ही सुना है।

1973 में जब मैं बीएचयू में पढ़ रहा था पीएसी विद्रोह हुआ था। हमलोग तमाशा देखने लंका से सामने घाट पीपे का पुल सायकिल से पार कर देखने गयं थे, पर जब किले के पास पुलिस ने दौड़ाया तो वापस भागे। दूसरे दिन अखबारों से सारी बात पता चली। रामनगर, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर आदि स्थानों की पीएसी वाहिनियों में जवानों ने हथियार उठा लिये थे, और सेना को कमान संभालनी पड़ी थी। सेना के अफसर जवान भी मरे थे और पीएसी के भी अफसर जवान मारे गए थे। तब कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री थे और एके दास आईजीपी थे। तब डीजी का पद नहीं बना था। आईजी ही सर्वोच्च अफसर होता है। सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, और एके दास को हटना पड़ा। पर यह विद्रोह किसी अपराध में लिप्त अभियुक्त पुलिस जन को बचाने के लिये नहीं बल्कि पीएसी को मिलने वाली सुविधाओं, के कारण था। बाद में पीएसी का बजट बढाया गया, सुविधाएं बढ़ी और कार्यप्रणाली में सुधार के लिये कदम उठाए गए। तब एक संगठन पुलिस परिषद का भी गठन हुआ था, जिसे सरकार ने अवैध घोषित कर रखा है। 1973 के विद्रोह के बाद कई पीएसी वाहिनियों को भग्न कर दिया गया। उनके स्थान पर नयी वाहिनियां गठित की गयी। विद्रोह की वाहिनियों को भंग किये जाने की एक सैन्य परंपरा भी है। ऐसे अनुशासनहीन विद्रोह न केवल पुलिस अनुशासन की गरिमा गिराते हैं, बल्कि वे विभाग पर एक प्रकार से काले धब्बे हैं।

लखनऊ की घटना न केवल अचंभित करती है बल्कि वह एक खतरनाक वायरस का भी संकेत देती है। जब हम लोग नौकरी में आये थे तो, पीटीसी जिसे तब अकादमी नहीं कहा जाता था में विस्तार से इस विद्रोह के कारणों को बताया गया था। अनुभवी और पुराने अधिकारियों के अनुसार, जब अफसर और मातहत में आपसी विश्वास का अभाव होने लगता है तो यह सारी समस्याएं और ऐसी अनुशासनहीनता की घटनाएं होने लगती हैं। पहले अफसर और मातहत के बीच का संबंध एक परिवार और उसके मुखिया के बीच का आत्मीय संबन्ध होता था। अनुशासन का अर्थ मातहत को केवल नियंत्रित करना ही नहीं है, बल्कि उसकी सारी निजी और विभागीय समस्याओं को सुनना तथा उसका निदान ढूंढना है। पुलिस प्रबंधन किसी कंपनी के एचआर के प्रबंध की तरह नहीं किया जा सकता है। यहां मानव प्रबंधन तो है पर जिसे नियंत्रित करना है वह एक प्रशिक्षित शस्त्र चालक और शस्त्र धारक भी है। यहां अनेक आदेश निर्देश समय असमय पर मौखिक ही दिए जाते हैं। अफसर को अपने दिए आदेश की जिम्मेदारी लेनी ही होगी, चाहे वह आदेश जुबानी हो या लिखित। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब यह आदेश अनुचित होता है और बैक फायर हो जाता है। उस समय नेतृत्व का यह गुण और दायित्व है कि वह उस आदेश की भूल को स्वीकार करे। इसे डांट डपट कर, अनुशासन के आवरण में लपेट कर नहीं रखा जा सकता। मातहत को अगर यह विश्वास हो जाय कि उसके अधिकारी उसके साथ हैं तो न केवल उसका मनोबल बढ़ता है बल्कि वह अपने दायित्व का निर्वहन भली प्रकार से कर बैठता है। जब वह यह मानने लगता है कि अफसर पल्ला झाड़ देगा तो वह स्वत: अनुशासनहीन होने लगता है।

पुलिस में कोई ट्रेड यूनियन जैसा संगठन नही है और न ही ऐसे संगठनों का अस्तित्व होना चाहिये। ऐसे संगटन कुछ पुलिसजन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही जगायेंगे। वे राजनीतिक दलों के लिये जो जाति और धर्म के आधार पर अपना खेत ढूंढते है के लिये एक चारागाह ही बन जाएंगे। हो सकता है ऐसे संगठन के कुछ पदाधिकारियों भले ही कल्याण हो जाँय पर पुलिस बल और विभाग का हित बिल्कुल भी नहीं होगा। जब पुलिसजन के पास सेफ्टी वाल्व जैसा कोई समस्या निवारण का मेकेनिज्म नहीं है तो यह जिम्मेदारी पुलिस की इकाई के प्रभारी, जैसे जिले के एसपी, और बटालियन के कमांडेंट की है कि वह सभी मातहत पुलिसजन से न केवल संवाद बनाये रखे बल्कि उनकी निजी और विभागीय समस्याओं का भी निराकरण करे। पुलिस विभाग भी समय समय पर ऐसे आदेश निर्देश जारी करता रहता है और उचित धन भी देता है, जिससे कल्याणकारी योजनाएं चलायी जाती। विभाग के प्रमुख का यह गुरुतर दायित्व है कि एक आपसी भरोसे का सेतु बना रहे।

लखनऊ की काला फीता हांथो में लगाने की घटना को सामान्य प्रतिरोध समझने की भूल नहीं करना चाहिये। विवेक तिवारी हत्याकांड में कल्पना तिवारी को मुआवजा मिल जाने और उनको नौकरी मिल जाने से इस अपराध का शमन नहीं हो जाता है। मुआवजा कोई अर्थदंड नही है बल्कि सरकार की एक सदाशयता है। पर हत्या तो हुयी ही है। अभियुक्त जेल में है । अभी तफ्तीश चल रही है। उसका कहना है कि उसने आत्मरक्षार्थ फायर किया है। यह काम अब विवेचक का है कि वह तथ्यों का अनुसंधान करे कि सच क्या है और उसे अदालत ले जाये। पर सिपाहियों का यह कृत्य कि वे मुल्ज़िम के पक्ष में काली पट्टी लगाएं सर्वथा अनुचित है। अगर उन्हें लगता है कि मुल्ज़िम को जानबूझकर फंसाया जा रहा है और एसआईटी विवेचना में निष्पक्षता नहीं बरत पा रही है तो वे सरकार या डीजीपी से विवेचना एजेंसी बदलने के लिये अपनी बात रख सकते हैं, न कि काली पट्टी बांध कर विरोध करें।

विवेचना, सीबीसीआईडी से हो सकती है और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सीबीआई से भी हो सकती है। कल अगर इस तरह पुलिसजन झंडे लेकर सड़क पर हर उस विवेचना में जिसमे कोई पुलिसजन अभियुक्त है के पक्ष में खड़े हो जाय तो कानून व्यवस्था की लंबी लंबी बातें करना तो भूल ही जाइये, हम एक उद्दंड और अनुशासन हीन पुलिस बल बन कर रह जाएंगे। इस घटना को नजरअंदाज करना एक प्रकार का अशनि संकेत है। इसकी अलग से जांच कराकर कार्यवाही की जानी चाहिये।

पुलिस की योगी छाप गुंडई.....

पेज एक का शेष

डेढ़ साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश पुलिस कर चुकी है जबकि इनमें से एक भी मामले में स्वतंत्र जांच नहीं की गयी।

यहाँ तक कि विनीत तिवारी मामले में भी, जहाँ वे गलती स्वीकारने का ढोंग कर रहे थे, अपराध की छानबीन से छेड़छाड़ की गयी। डीजीपी का माफीनामा भी, जो पुलिस को नैतिक उपदेश देने तक सीमित है, पूर्णतया गैरकानूनी एनकाउंटर संस्कृति के चलन पर एकदम खामोश है। क्या नैतिकता और वैधानिकता परस्पर विरोधी खेमा हुए ? जबकि 'गलती' से सबक और तदनुसार पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन न्यूनतम पहल होनी चाहिए थी। दरअसल, औपनिवेशिक निर्मिति के घेरे से बाहर आकर संवैधानिक निर्मिति की यात्रा का पहला निर्णायक कदम उठाने से भी हमारी पुलिस अभी कोसों दूर है।

हत्यारोपी पुलिस वालों को लखनऊ में विनीत तिवारी की कार का पीछा करके रोकना महज इसलिए जरूरी लगा क्योंकि उनके साथ एक महिला भी थी; उन पर पुलिस की मोटर साइकिल में टक्कर मारने का आरोप मढ़ा गया ताकि 'ठोक दे' की नृशंसता छिप सके। योगी इसे एनकाउंटर नहीं कहते लेकिन कभी अपने परिवार से पूछिए- मल्टीनेशनल कंपनी के इस बड़े एग्जीक्यूटिव की तरह, किसी शाम काम से घर लौटते हुए, पुलिस के हवाई शक के चलते बीच सड़क पर आपके मारे जाने की आशंका क्या उन्हें सुरक्षित बनायेगी ?

आइये इसी दृश्य को आगे बढ़ायें। दूर अलीगढ़ में नौशाद और मुस्तकीम नामक दो गरीब मुस्लिम नौजवानों को पुलिस दो दिन पहले हुयी एक बेसुराग हत्या के संदेह में 16 सितम्बर को उनके घर से उठा लेती है, 18 सितम्बर को उन पर इनाम घोषित करती है ताकि 20 सितम्बर को उन्हें 'लाइव' एनकाउंटर में मारा जाता दिखा सके। योगी, इसे एनकाउंटर कहते हैं। बेशक प्रदेश के दो अलग क्षेत्र और दो अलग प्रकरण, लेकिन दोनों में एक-सी ठोक दे मानसिकता।

सत्ता राजनीति के जातिवादी मंचन और पुलिस की औपनिवेशिक जड़ों के योगी गठजोड़ का कोई भविष्य नहीं है। पुलिस के अपराधीकरण के रास्ते से अपराध सफाये की मंजिल तय करने की योगी मुहिम एक दिवा स्वप्न से अधिक कुछ हो भी नहीं सकती। विवेक तिवारी हत्याकांड को जातिवादी राजनीति का आईना मत बन जाने दीजिये। हाँ, इसमें न्यायिक विवेक का प्रशासनिक आईना होने की संभावना जरूर है, जिसमें हर पुलिस एनकाउंटर को देखा-परखा जाना चाहिये।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

गतांक की चीर-फ़ाड़

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी को राफ़ेल की कीमतों पर एतराज जताने की मिली सज़ा

मज़दूर मोर्चा के 30 सितम्बर-6 अक्तूबर 2018 के अंक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय स्तर के ज्वलंत व महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक समाचार प्रकाशित हुये हैं। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद द्वारा राफ़ेल सौदे के मामले में खुलासा करने से मोदी सरकार तथा स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है।

ओलांद ने एक इंटरव्यू में कहा, 'राफ़ेल सौदे के दौरान भारत सरकार ने ऑफसेट करार के लिये सिर्फ़ एक कंपनी का नाम सुझाया था और वह थी रिलायंस डिफेंस। हमारी सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था और भारत सरकार ही थी, जिसने दसाल्ट एविएशन के साथ बातचीत के लिये इस ग्रुप का नाम सुझाया।' रिलायंस डिफेंस अनिल अम्बानी की कम्पनी है और विपक्ष विशेषकर कांग्रेस शुरू से ही मोदी सरकार पर सौदे में अम्बानी ग्रुप को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा रहा है। 'एन ईवनिंग इन पेरिस-डील, डीलर और पीएम मोदी' में ओलांद के खुलासे के संदर्भ में साठ साल पुरानी विमान बनाने की अनुभवी कम्पनी सरकारी उपक्रम हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को दरकिनार करके एक नई अनुभवहीन रिलायंस कंपनी के साथ राफ़ेल डील करने, यूपीए काल में किये गये सौदे से ज़्यादा कीमत पर राफ़ेल लड़ाकू विमान खरीदने आदि का सटीक विश्लेषण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के पूंजीपति मित्र अनिल अम्बानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिये एचएएल को लगभग 30,000 करोड़ रुपये के ऑफसेट कांट्रेक्ट से वंचित किया गया। इससे मोदी सरकार की मिलीभगत और सांठ गांठ का खुलासा हुआ है।

परंतु मोदी सरकार के प्रवक्ता सवालों का जवाब देने की बजाये कुतर्कों और झूठ का सहारा ले रहे हैं। वित्त मंत्री अरूण जेटली व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस खुलासे के बाद सरकार के बचाव में ओलांद की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं।

'रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी की राफ़ेल की कीमतों पर एतराज जताने की मिली सज़ा' में रक्षा मंत्रालय की कान्ट्रैक्ट नेगोसिएशन कमेटी के सदस्य रक्षा मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी और एक्विजीशन मैनेजर राजीव वर्मा (वायु सेना) द्वारा राफ़ेल डील की बेंचमार्क कीमत को लेकर तैयार किये गये नोट में लिखित एतराज का पर्दाफ़ाश किया गया है। राजीव वर्मा का कहना था कि 126 राफ़ेल विमानों की खरीद के पुराने प्रस्ताव की कीमत से 36 राफ़ेल विमानों की खरीद की कीमत बहुत ज़्यादा है। राफ़ेल की बेंच मार्क कीमत को निर्धारित करने के लिये उसकी तुलना 18 तैयार राफ़ेल विमानों से होनी चाहिये जो पुराने प्रस्ताव के अनुसार उड़ान की स्थिति में फ्रांस से आने थे। इसके अतिरिक्त वर्मा ने विमान की कीमत में 20 प्रतिशत की कटौती के बारे में भी नोट में लिखा था। परंतु इस नोट को दर किनार कर दिया गया और राजीव वर्मा के छुट्टी पर जाने के बाद डायरेक्टर जनरल स्मिथ नागराज के आने पर सितम्बर 2016 में रक्षा मंत्री मनोहर परिकर के नेतृत्व में बनी डिफेंस एक्विजीशन कौसिल ने राफ़ेल करार पर अपनी सहमति दे दी। चर्चा है कि राजीव वर्मा द्वारा किये गये एतराज के कारण उन्हें छुट्टी पर भेजा गया। पहले से लगभग तीन गुणा कीमत देने के राफ़ेल करार पर मोदी सरकार चारों ओर से संदेह के घेरे में आ गई है।

राफ़ेल डील पर राजनीतिक संकट का सामना कर रही मोदी सरकार ने अब अपने बचाव में वायु सेना प्रमुख एयर चीफ़ मार्शल बी.एस. धनोआ को मैदान में उतार दिया। वायु सेना प्रमुख ने दसॉल्ट कंपनी से अंबानी की रिलायंस कंपनी से राफ़ेल डील का समर्थन करते हुये कहा कि राफ़ेल विमान की कीमत पुराने प्रस्ताव से कम है लेकिन यह नहीं बताया कि राफ़ेल का पहले क्या दाम था और अब कितना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत का चौकीदार होने का दावा किया था। परन्तु मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं तो अपने साथ किसी न किसी पूंजीपति मित्र को साथ ले जाते हैं और उससे किसी न किसी सौदे का करार हो जाता है, जैसे गौतम अडानी को आस्ट्रेलिया लेकर गये वहां उससे एक प्रोजेक्ट का करार हो गया और फ्रांस में अनिल अम्बानी और अडानी को साथ लेकर गये वहां दसॉल्ट कंपनी का अंबानी की कंपनी से सौदा हो गया। मोदीजी की योजना मेक इन इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया का सबसे ज्यादा लाभ अंबानी की कंपनी रिलायंस नेवल (वर्तमान रिलायंस डिफेंस) को हुआ। अब रिलायंस डिफेंस को इजरायल, अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूएई, जर्मनी आदि से लाखों करोड़ के सौदे मिलने लगे, जिनका 'एक ढूंढो दस मोदी घोटाले मिलेंगे-यकीनन' में भंडा फ़ोड़ किया गया है। राजनीतिक गलियारों में इन सौदों में प्रधानमंत्री मोदीजी की मिलीभगत होने की चर्चा है।

'खबर (दार) झरोखा कहीं संघ के एजेंडे के शिकार तो नहीं हो रहे राहुल गांधी' में राहुल गांधी की मान सरोवर यात्रा, शिव भक्त राहुल, जनेऊ धारी राहुल, हर स्थान पर मंदिर में जाना आदि के संदर्भ में सटीक विश्लेषण किया गया है कि स्वगीय राजीव गांधी की तरह कहीं राहुल गांधी भी राष्ट्रीय सेवक संघ (संघ) और भाजपा द्वारा निर्धारित एजेंडे के शिकार न हो जाए और संघ की ध्रुवीकरण की राजनीति को और ध्यान दे दे। वास्तव में संघ की बेहद पिछड़ी विचारधारा है और उसे अपने अंध राष्ट्रवाद तथा मानवाधिकार विरोध के बरबक्स तथाकथित सांस्कृतिक मूल्यों और सनातनी गौरव का नैतिक चैंपियन बने रहना है। इसलिये राहुल गांधी व उनके सलाहकारों को संघ के एजेंडा से सावधान रहने की आवश्यकता है।

आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अपना वोट बैंक तैयार करने के प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को मुफ़्त इलाज देने के लिये 'आयुष्मान' योजना घोषित की है। ज़मीनी स्तर पर इस योजना को सफ़ल बनाने के लिये अभी कोई ठोस तैयारी नहीं की गई है, इसलिये जनता को भ्रमित करने के लिये प्रचारतंत्र का पूरा सहारा लिया जा रहा है, जिसकी फ़रीदाबाद के संदर्भ में 'आयुष्मान:इलाज भले ही न मिले, ढोल तो यूं ही बजता रहेगा' 'आयुष्मान भव: का आशीर्वाद किनको ?- मोदी की हर योजना की तरह आयुष्मान भारत भी एक छलावा निकला' में पोल खोली गयी है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव जोवल द्वारा तमाम ज़िलों के उपायुक्तों को दिये गये सख्त निदेर्शों के बावजूद ज़िले का कोई बड़ा अस्पताल (तथाकथित सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल) जैसे फ़ोर्टिस एस्कोर्ट, एशियन, मैट्रो, क्यूआरजी, सर्वोदय, ईएसआई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल आदि इसमें शामिल नहीं हुए हैं। इसलिये गरीब मरीजों को सरकारी अस्पतालों तथा छोटे निजी अस्पतालों पर निर्भर रहना होगा। गौरतलब है कि यह सुविधा केवल अस्पताल में भर्ती मरीज़ों को ही मिलेगी।

'मात्र 47 वर्ष में जर्जर हुई नेहरू कॉलेज की इमारत, 14 करोड़ में नई बनेगी-100-100 साल पुराने स्कूल, कॉलेज भी सलामत खड़े है में भ्रष्टाचार की शिकार नेहरू कॉलेज की बिल्डिंग की उचित समीक्षा की गई है। वे बिल्डिंगें जो स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश राज में बनी थी अथवा निजी संस्थाओं द्वारा बनाई गई थी आज भी बड़ी शान से खड़ी है, क्योंकि यह ईमानदारी के कारण था और उस समय भ्रष्टाचार भी सीमित था। विशेष ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान स्थानीय राजकीय महिला महाविद्यालय की बिल्डिंग के पीछे विद्यमान तत्कालीन नेहरू कॉलेज की बिल्डिंग अब भी सुरक्षित हैं जहां लड़कियों की कक्षायें लगती हैं। नेहरू कॉलेज की वर्तमान बिल्डिंग जो जर्जर घोषित हो चुकी है का निर्माण 47 वर्ष पहले सरकारी विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया था जो उनके भ्रष्टाचार की भेंट चढ गई है। केवल 47 वर्ष पहले बनी बिल्डिंग का जर्जर हो जाना आश्चर्यजनक है। इसके अतिरिक्त इस बिल्डिंग के बदले में 15000 छात्रों की क्षमता वाली नई बिल्डिंग बनाने की योजना अव्यवहारिक लगती है।

राफ़ेल लड़ाकू विमान बनाने का सौदा मोदी सरकार द्वारा फ्रांसीसी कम्पनी से अनिल अंबानी की कंपनी को पहले से तीन गुणा दाम में दिलाने पर 'गली-गली में शोर है, क्या चौकीदार ही चोर है ?' कार्टून द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईमानदारी और विश्वसनीयता पर तीखा व्यंग्य किया गया है।